

ISSN : 0973-1210

सामाजिक शोध पत्रिका JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH

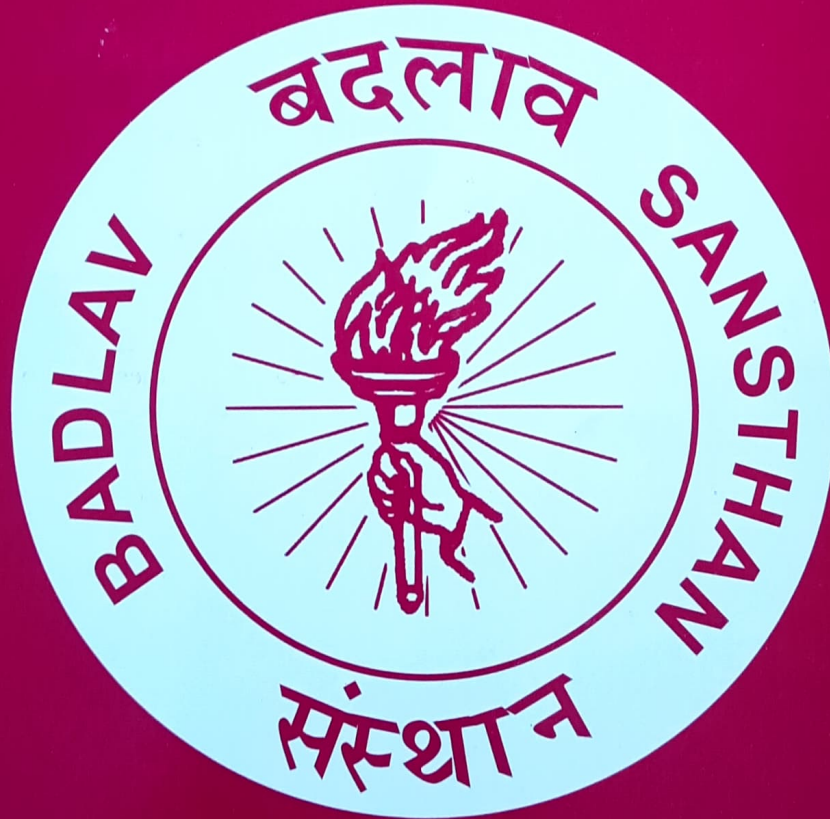
Volume : XV

No. : II

Year : December, 2019

REFERRED JOURNAL

Affiliated to International Social Sciences Network



RESEARCH JOURNAL PUBLISHED BY BADLAV SANSTHAN

ADVISORY BOARD

- Adv. Fateh Singh Mehta** : Legal Advisor, Ex. Chairman, Rajasthan Bar Council
Prof. Hemant Kothari : Dean, P.G. Studies, Pacific University Udaipur (Raj.)
Prof. K K N Sharma : Head, Deptt. of Anthropology, Dr. H.S. Gour, Central University, Sagar, M.P.
Prof. Arvind Chauhan : Head, Deptt. of Sociology, Barkatullah, University, Bhopal (M.P.)
Prof. Vishnu Sarvade : Professor, Deptt. of Hindi, Mumbai University, Maharashtra
Prof. Desraj : Professor: Deptt. of Sociology, M.D. University, Rohtak, Haryana
Prof. Sudha Chaudhary : Head, Deptt. of Philosophy, MLSU, Udaipur, Rajasthan
Prof. Achla Gakkhar : Professor, Deptt. of Home Sc., Extn, Edu., Dr. Ambedkar University, Agra U.P.
Prof. Amman Madan : Professor, Deptt. of Socio. & Anthro. Azim Prem Ji University, Banglore (Kt)
Prof. F. L. Sharma : Professor, Deptt. of Extension Education, MPUAT, Udaipur, Rajasthan
Prof. S.S. Sisodia : Professor, Deptt. of Extension Education, MPUAT, Udaipur, Rajasthan

EDITORIAL BOARD

- Prof. R. H. Makwana** : Chairman
Dr. Shri Ram Arya : Editor-in -Chief
Dr. Suresh Salvi : Associate Editor
Dr. Raju Singh : Executive Editor
Dr. Hemlata Verma : Managing Editor

PEER REVIEW BOARD

- Dr. Monika Dave** : Chairman
Dr. Anju Beniwal : Secretary
Dr. M.K. Dashora : Convener
Dr. Lala Ram Jat : Coordinator
Dr. Meeta Solanki : Panel Advisor

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

- Dr. Gaurang Jami** : Assoc. Prof., Deptt. of Sociology, Gujarat University
Dr. A. R. Lohia : Assoc. Prof., Deptt. of Psychology, Govt. M.G. College, Udaipur, Rajasthan
Dr. Vandana Verma : Assoc. Prof., Deptt. of Economics, Govt. M.G. College, Udaipur, Rajasthan
Dr. Arun Kumar : Assoc. Prof., Deptt. of Pl.Sc., S.R. Govt. P.G. College, BandiKui, Rajasthan
Dr. Khushpal Garg : Asstt. Prof., Deptt. of English, M.L.S.U., Udaipur, Rajasthan
Dr. Ramkesh Meena : Deputy Librarian, Central Library, M.L.S.U., Udaipur, Rajasthan
Dr. Maneeram Meena : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, SMB, Govt. P. G. College, Nathdwawra, Raj.
Dr. Kunjan Acharya : Asstt. Prof., Deptt. Of Journalism & Mass Commn., MLSU, Udaipur, Raj.
Dr. Jyoti Gautam : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, M.G. Girls P.G. College, Udaipur, Raj.
Dr. Shruti Tandon : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, M.G. Girls P.G. College, Udaipur, Raj.
Dr. Ranjeet Meena : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, Govt. College Kherwada, Rajasthan
Dr. Rajkumari Ahir : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, M.L.S.U., Udaipur, Rajasthan
Dr. Kamini Dashora : Asstt. Prof., Deptt. of Sociology, Adiwasi College, Tribal Uni., Gujarat
Dr. Rashami Singh : Asstt. Prof., Deptt. of Psychology, MLSU, Udaipur, Raj.
Dr. Noorjahan Mansoori : Lecturer, Deptt. of Rural Sociology, VBRI, Udaipur, Rajasthan
Dr. Nirmla Dangi : Lecturer, Deptt. of Rural Sociology, VBRI, Udaipur, Rajasthan

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, प्रधान सम्पादक एवं मुद्रक डॉ. श्रीराम आर्य द्वारा उदयपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित

ISSN : 0973-1210

सामाजिक शोध पत्रिका

JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH

Volume :XV

No. : II

Year : December, 2019

REFERRED JOURNAL

Affiliated to International Social Sciences Network



A HALF YEARLY RESEARCH JOURNAL PUBLISHED BY BADLAV SANSTHAN

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	भारत में गरीबी: लैंगिक भेदभाव और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी - अर्जुन लाल जाट	5-13
2.	भारत में निर्धनता : आयाम, प्रभाव व समाधान - रामअवतार जाट	
3.	अनुसूचित जनजाति के वाणिज्य संकाय के छात्रों की अध्ययन आदतों, आकांक्षा स्तर व शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन - डॉ. मोनिका बाबेल	14-19 16-19
4.	महाराणा प्रताप कालीन संस्कृति, कृषि एवं निर्माण कार्य - डॉ. यशपाल बरण्डा	
5.	भारत में निर्धनता का आधार - डॉ. निर्मला डाँगी	20-22
6.	गरीबी को समाप्त करने हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किये गये प्रयास - डॉ. मोनिका बाबेल (जारोली)	23-26 27-30
7.	ग्रामीण व शहरी गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन - डॉ. नूरजहाँ मंसूरी	31-34
8.	जनजातीय विकास में गैर सरकारी संगठनों का योगदान - गौतमलाल मीणा	35-38
9.	निर्धनता पर राजनीति एवं मानवाधिकार - डॉ. रजनी धामाई	37-39
10.	जनजातीय क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का योगदान - शक्ति सिंह राठौड़	40-42
11.	आर्थिक विषमता सामाजिक विषमता की जननी है: मृच्छकटिकम् के परिप्रेक्ष्य में - डॉ. रेनु पालीवाल	43-44
12.	गरीबी के कारण एवं दुष्प्रभाव - डॉ. मनीराम मीणा	45-48
13.	भारत में गरीबी के कारण एवं समाप्त करने के लिए सुझाव - गीता मीणा	47-49
14.	देवजी की फड़ वाचक कलाकार- 'भोपा' (एक परिचय) - अंजली	50-52
15.	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से नारी सशक्तिकरण - डॉ. प्रतिभा शर्मा	53-54
16.	माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की दुश्चिंता का उनके व्यक्तित्व तथा सामंजस्य के साथ सम्बन्ध का अध्ययन - डॉ. अनूपा शर्मा	55-57
17.	गरीबी और शिक्षा - राकेश सैनी	58-60
18.	विकलांग विद्यार्थियों के मानव अधिकारों के हनन का एक शोधपरक विश्लेषण - परेश त्रिवेदी	61-62
19.	भारत में विभिन्न युगों के दौरान भूमि का महत्व एवं भू-व्यवस्था - डॉ. निर्मला डाँगी	63-67
20.	गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज की भूमिका - दाना राम रांगी एवं डॉ. राजु सिंह	68-70
21.	Does Economic scale of family affects Emotional Competencies? - A study related to Youth - Dr. Rashmi Singh	71-74
22.	Study the Effect of Socio Economic Status (Upper & Lower) on Adjustment Level of Adolescents - Dr. A.R. Lohia & Miss Jyotsana Meghwal	75-77
23.	A Present Status of Vocational Education, Skill Development and Labour Force in India - Chanchal Jain & Dr. Shashi Shanchiher	78-83
24.	Impact of FDI on Various Sectors During 2017-18 - Prahalad Dhaker	84-87
25.	Performance of Livestock Sector and its Contribution to the Economy of Rajasthan - Dr. Mahendra Ranawat & Paramjeet Kunwar Deora	88-92
26.	Olfactory Experience as Trump Card in Retail Dr. Lavika Jaroli & Ms. Bhart Jain	93-96

गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज की भूमिका

दाना राम रांगी *

डॉ. राजु सिंह **

गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य मानवीय जीवन के समस्त पहलू का विकास करने के लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें गरिमा, गौरवमय जीवन व्यतित करने के लिए प्रेरित एवं अवसर प्रदान करना, गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली, विभिन्न माध्यमों द्वारा संचालित होती है। जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता वर्द्धन, कार्यक्रम नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आजीविका कार्यक्रम, अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर कल्याणकारी जानकारी उपलब्ध करवाना। इत्यादि। विभिन्न माध्यमों से इन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठन की भूमिका नागरिक समाज संगठन सामाजिक समूहों से मिलकर बने होते हैं। जो मुख्यतः स्वैच्छिक सामाजिक संघों/व्यावसायिक संघों, संरचनाओं में निहित सामाजिक आन्दोलनों के विविध संग्रह समूह होता है।

कई विकसित और विकासशील देशों की तरह भारत में नागरिक समाज संगठन ऐसे प्रयासों में केन्द्र-राज्य तक पहुंच गया है। जो समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से सामाजिक विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों में योगदान करते हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि सामाजिक विकास के उपर्यो की शांति और प्रगति सुनिश्चित करने में नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तार किया है और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में राष्ट्र-राज्य के प्रयासों में सहयोग करने और योगदान करने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत किया है।

भारत में नागरिक समाज के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर जनता और सरकार का ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता है, जिसका समाज के कमजोर वर्गों को सामना करना पड़ता है। गरीबी के कारणों का पता लगता है और उनकी चिंता व्यक्त करती हैं। कई विकास के मुद्दों को संबोधित करते हुए जो राष्ट्र निर्माण के उपायों के लिए आलोचनात्मक महत्वपूर्ण हैं।

नागरिक समाज संगठन -पेशेवर संघों, सामाजिक सेवा संगठनों और गैर लाभकारी स्वैच्छिक संस्थाएं और वित्तीय अभिकरण, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए सभी राज्य-आरंभ की योजनाओं के नियोजनों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भागीदार भाग लेने वालों में समाज के अति पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं और बच्चों के विकास कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य पहल की योजनाओं के क्रियान्वयन कार्यक्रमों और योजनाओं निर्माण में भाग लेने वाले और सहभागी के रूप में अब मान्यता प्राप्त होते हैं।

समाज में इन वर्गों की समस्या निवारण हेतु वास्तव में केवल राज्य के कार्यों, कृत्यों-सरकार की कार्यप्रणाली द्वारा निपटना बहुत ही कठिन है।

नागरिक समाज वर्ग, व्यापक और बड़े पैमाने पर है। गैर सरकारी संगठनों के निर्माण में दिखाई पड़ता है। कई समस्यागत सामाजिक मुद्दों और निवारण के लिए हमेशा सबसे आगे रहता है। गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों का वर्ग हाल में नहीं दिखलाई पड़ता है। बल्कि ये काफी पुराने समय में इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं। शायद ऐसा प्रतीत होता है कि यह उतना ही पुराना है जितना की मानव सभ्यता पुरानी है। कहने का तात्पर्य का इतिहास-प्रारम्भ मानव सभ्यता के उद्भव के साथ से ही माना जाता है। ये मानवता, पर दयालुता के द्रव को उत्पन्न कर उनकी समस्याओं को निपटाने में योगदान करता है।

मानव हृदय में निहित करुणा एवं दया के द्रव को बाहर आता है। यह उनकी एन.जी.ओ. की शक्ति से उत्पन्न होता है। एनजीओ असहाय की मदद, निरुत्साहित की सेवा-देखभाल की मानवीय प्रवृत्ति से शक्ति उत्पन्न होती है। असुरक्षित को सुरक्षित करना एवं असशक्त को सशक्त करने की श्रेणी के रूप में प्रासंगिक है।

यह वर्ग प्रत्येक समाजों में विद्यमान होता है। प्राचीन, आधुनिक, आमुखी या पश्चिमी देशीय समाजों, विकसित देशों एवं विकासशील देशों में हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है। गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों की नवीन परंपरा एक विरासत के रूप में क्रमिक रूप से चली आ रही है। ये गैर सरकारी संगठन भारत में नागरिक समाज की विशिष्ट विशेषता है। वर्तमान में स्वैच्छिक क्रियाओं की परंपरा गैर सरकारी संगठनों के रूप में दिखलाई पड़ती है।

ये गैर सरकारी संगठन समाज में जाति-भेदभाव, धर्म, लिंग, के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं समाज को भी भेदभाव रहित दृष्टि परिवर्तन के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित करते हैं। और समाज को सहज भाईचारा, न्यायसंगत, जाति, धर्म, लिंग एवं उनकी सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक, स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इन एनजीओ का प्रमुख उद्देश्य समाज में उपस्थित धिनौनी सामाजिक कुरीतियों को समापन/समाप्त कर समाज को इस प्रकार सामाजिक प्रथाओं, अस्पृश्यता, सती प्रथा, विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, जैसी सामाजिक बुराईयों से समाज को मुक्त करता है इस प्रकार नागरिक सामाजिक संगठनों का आधार मार्गदर्शक सिद्धांत-दान पुण्य परमार्थ सेवा श्रुषा है।

* Research scholar Dept. of Sociology UCSSH Mlsu Udaipur (Raj.)

** Assistant Professor Dept. of Sociology UCSSH Mlsu Udaipur (Raj.)



इन गैर सरकारी संगठनों के आरम्भकर्ताओं या संस्थापकों का लक्ष्य धन अर्जन या ख्याति अर्जन न होकर, परमार्थ समाज सेवा जो वेतन मुक्त एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण युक्त होता है। ये महाशय सेवा कार्य के बदले में किसी प्रकार की आशा नहीं रखते थे। वर्तमान में अक्सर उनमें से कुछ थोड़ी बहुत सामाजिक प्रशंसा एवं संतुष्टि के लिए लालसा रखते हैं। प्राचीन कालीन दिनों में इस नागरिक सामाजिक संगठनों का स्वरूप आधुनिक के गैर सरकारी संगठनों की भांति तार्किकता रहित था। उन दिनों इन संगठनों द्वारा कार्य प्रवृत्ति की कुछ सीमाएं होती थी। जो व्यक्तिवादी, नैतिकवादी, और पैतृक सिद्धांत पर आधारित होती थी। जो वर्तमान में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण में प्रासंगिक नहीं है। प्राचीनता में उनकी कार्य पद्धति अक्सर छुटपुट सामाजिक और असंगठित थी। इसने समकालीन दिनों में विकास लक्ष्यों और लोगों के सशक्तिकरण के समकालीन दृष्टिकोण को सीधे अंगीकार नहीं किया है।

आधुनिक काल में समाज सेवा का दायरा समाज के कमजोर एवं कमजोर वर्गों के विकास और सशक्तिकरण जैसे शब्दों से काफी व्यापक हैं जो नागरिक समाज के दायित्वों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस जिम्मेदारी पूर्वक किये जाने वाले कार्यों से ही गैर सरकारी संगठनों की प्रासंगिकता फलीभूत होती है इसमें कल्याण का ही राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज हमारे देश में विभिन्न स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और वैश्विक गैर सरकारी संगठन हैं जो लगभग मानवीय जीवन एवं प्राकृतिक जीवन के सभी स्तरों पर संकाय पर काम कर रहे हैं। ये केवल मानवीय मूल्यों का विकास ही नहीं संपूर्ण मानवीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। अर्थात् लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके इस प्रकार देश में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों का जीवन लोगों की सद्भावना पर आधारित हैं और उनके सहजकर्मी अनुनयन के साथ समाज की विपरीतता पर दबाव और प्रचार-प्रसार करते हैं। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समाज के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की वृत्तियों को सुधार के साथ बदलते हैं। और समाज में विकास बाधित सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भी प्रभावित करते हैं और समाज में स्थित पूर्वाग्रहों को भी ध्वस्त करते हैं। जो केवल राज्य आधारित कानून द्वारा नहीं किया जा सकता है।

ये गैर सरकारी संगठन समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अति संवेदनाशील होते हैं। इनका सिद्धांत या प्रमुख उद्देश्य— समाज के कमजोर वर्ग—अनुसूचित जाति, जनजाति, वृद्ध महिलाएं बच्चे, अनाथ, असहाय, परित्यक्ता, पीड़िता से उनकी निकटता और समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता में निहित है। राज्य द्वारा लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के व्यक्तिगत पहुँच के मुद्दों में गैर सरकारी संगठनों की पहुँच एवं पकड़ अच्छी होती है समाज राष्ट्र, राज्य,

समाज समुदाय के विकास की प्रक्रिया में लोगों के साथ-साथ लाने हेतु प्रेरित करने में गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख विशेषता होती है। अर्थात् इनके पास इस कार्य हेतु दक्षता प्राप्त व्यवसायिक विशेषज्ञ भी उपलब्ध होते हैं।

गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को व्यक्तिगत स्वरूप देने की तुलना में अपेक्षाकृत महति भूमिका की स्थिति में होते हैं। गैर सरकारी संगठनों के दृष्टिकोण में लचीलापन उन समस्याओं के उचित समाधान का आविष्कार करने में मदद करता है जिसका वे सामना करते हैं वे लोगों की आवश्यकता को समायोजित कर सकते हैं गैर सरकारी द्वारा छोटे स्तरों, स्थानीय सहजकर्मी सेवाओं के ह्रास पूर्ति करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। उन्हें गरीबों तक पहुँचने के लिए लचीला, सहभागितापूर्ण, सस्ता, और बेहतर माना जाता है।

अतः स्वैच्छिक क्षेत्र लोगों को संगठित करने और सर्वांगीण विकास के लिए आंदोलन उत्पन्न करने और समर्थन करने के लिए प्रभावी कदम होता है। भारत में आम जनता के लिए स्वैच्छिक कार्य करने की गौरवशाली परंपरा है। यह सामुदायिक भागीदारी और लोगों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से हाल के दिनों में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। स्वैच्छिक क्षेत्रों ने स्थानीय, विविध, विकासात्मक मुद्दों को सरल तरीकों से उत्प्रेरित किया है। वर्षों से गैर सरकारी संगठनों ने लोगों की उभरती समस्याओं और संकेतों के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाएँ शुरू की हैं। ताकि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की सेवा—सहायता और सहायता प्रदान की जा सके। गैर सरकारी संगठनों द्वारा जरूरतमंदों की सेवा और मदद के जूनून के साथ यह जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना। भारतीय स्वैच्छिक आंदोलन की एक विशिष्ट विशेषता है इन लोगों की सेवा, मदद, देखभाल, करुणा जैसी वृत्तियाँ हमारी परंपरा हैं जिससे इन संगठनों की जड़ों को और ताकत मिलती है।

विगत 50 वर्षों से भारत एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र रूप से आर्थिक विकास की दौड़ अग्रचर है। इसने काफी हद तक आर्थिक रूप से प्रगति की है। काफी मात्रा में साक्षरता को बढ़ावा देने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, अवसंरचनात्मक और संचार सुविधाओं में सुधार करने में और अनाधिकृतकाल की पीड़ा से भी उभरने में निजात पाई है। इस प्रकार विकास विरोधी समस्याओं को समाप्त कर दिया है। किसी भी देश में आर्थिक विकास की तीव्रता उनके नये उभरते भरोसेमंद व्यवसायों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी जैसी जटिलता प्राप्त समस्याओं की एक जटिलता का सामना कर रहा है। साथ ही देश, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, पर्यावरणी, समस्याओं जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। छह साल से कम उम्र के देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं इसकी आधी आबादी से अधिक महिलाएं अशिक्षित अनपढ़ हैं। लोगों के पास बिजली

नहीं है। अधिकांश लोगों को सामाजिक-आर्थिक अन्याय, पर्यावरण में गिरावट और यहां कई अन्य मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की सख्त जरूरत है।

किसी भी राष्ट्र के सतत विकास एवं अभिन्न विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी वैचारिकी और मूल्यों आधारित विकास प्रक्रिया द्वारा संभव है। इस जंहा विकास की प्रक्रिया से रचनात्मकता के नये रूप विकसित हो सकते हैं। यहां पर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और जिम्मेदारियों महत्वपूर्ण हो जाती है।

देश में दलित, पिछड़ों, कमजोर वर्गों को समानता के पदों पर लाने, और उनके अधिकारों का लाभ उठाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए सामुदायिक कल्याण और विकास के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की अवधारण कोई नयी नहीं है।

बड़ी संख्या में ऐसे संगठन भी थे जो सहकारी आंदोलन के आधार पर सामने आए। भारत में गैर सरकारी संगठनों का उदय और वृद्धि तो स्वतंत्रता पूर्व से ही ईसाई मशीनरियों के समाज सुधार कार्यों से मानी जाती हैं लेकिन वृद्धि में तीव्रता 1980 के दशक के मध्य से बहुत अधिक दिखलाई पड़ती है। उनमें से कई विदेशी-वित्त पोषित संगठन हैं, कुछ को विशेष योजनाओं के तहत, सरकारों से धन मिलता है। कुछ संगठन दान पर अपने काम करते हैं। ये विदेशी स्त्रों या भारत सरकार से धन प्राप्त करने के हरक्षण इच्छुक रहते हैं। गैर सरकारी संगठन राज्य के लोगों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में मदद करते हैं ये सरकार पर अपनी नीतियों को लोगों के प्रति अधिक उन्मुख बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं और लक्षित क्षेत्रों के सथ स्वैच्छिक क्षेत्र में लक्ष्य के अनुरूप में शामिल होकर जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं सरकार की विभिन्न योजनाओं के उपर नजर रखते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने वैकल्पिक और अभिनव प्रारूप बनाए हैं। और अभी तक प्रगति की प्रक्रिया में व्यवसायिक एवं तकनीकी क्षमताओं का एहसास करने के लिए प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश की है। उनके मिशन एवं दृष्टि के अनुसार मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों ने ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, रोजगार सृजन, कृषि, विकलांगों के लिए सेवाएं आदि। सांस्कृतिक विरासत, लोक संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा की स्वदेशी प्रणाली परंपरागत चिकित्सा सेवा, कृषि, पर्यावरणीय क्षेत्रों को भी वे पोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी के द्वारा-विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता। प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक गड़बड़ी के दौरान, उन्होंने पीड़ित मानवता के लिए सेवाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

गैर सरकारी संगठनों के उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। उनमें से अधिकांश के विशिष्ट उद्देश्य प्रतीत होते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार और व्यस्क शिक्षा को बढ़ावा देना, बालश्रम का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता एक विशेष क्षेत्र में कृषि भूमि का उचित वितरण बंधुओं मजदूरी, सांप्रदायिक सौहार्द आदि से राहत प्रदान करवाना। जबकि प्रत्येक गैर सरकारी संगठन उसे सीमित उद्देश्य जो वर्तमान में जारी रख सकता है अधिकांश गैर सरकारी संगठनों ने लोगों में जागरूकता को विकसित किया है। कि वे लोकतंत्र में लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा हैं जिसमें राजनीतिक शक्ति वंचित वर्गों सहित लोगों के हाथों में आ जाएगी।

निष्कर्ष

गैर सरकारी संगठनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि लोकतांत्रिक लोकाचार की परिपक्वता और नागरिक समाज की ताकत का प्रतीक है। इस प्रकार इनके कार्य करने की प्रकृति से समझ सकते हैं कि व्यापक रूप से गरीब, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा, पर्यावरण मुद्दों, स्वास्थ्य समस्या की राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वैच्छिक आंदोलन को मजबूत करने और गैर सरकारी संगठनों और सरकार के बीच एक अधिक सार्थक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। देश में बहुत से राज्यों द्वारा गैर सरकार संगठनों को विकास की प्रक्रिया में सहभागिता हेतु आमंत्रित एवं प्राथमिकता दी जाती है।

संदर्भ सूची

1. राय, राजेन्द्र चन्द्रकान्त (2010) "गैर सरकारी संगठन स्थापना, प्रबंधन, और परियोजनाएं" राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली।
2. जोयल एस जी आर भोस "गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण विकास सिद्धांत" प्रैक्टिस अवधारणा पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
3. पाठक बिंदेश्वर (2010) विकेन्द्रिकृत राज्य में गैर सरकारी संगठन की भूमिका और नागरिक समाज, नई दिल्ली,
4. सिंह, रामगोपाल. (2010) "सामाजिक न्याय और दलित संघर्ष" प्रकाशन, राज. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, प्लॉट नृ. 01 झालाना स्थानिक क्षेत्र- जयपुर
5. आवटे, गोपाल नारायण (2012) "गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली, सिद्धांत और व्यवहार" कल्याणी शिक्षा परिषद 3320-21 जोटवाडा दरियागंज नई दिल्ली।
6. मेहता प्रकाश चंद (1991) " गैर सरकारी संगठन और विकास" शिवा प्रकाशन, वितरक- उदयपुर (राज.)
7. मिश्रा, राजीव (2008) "स्वैच्छिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास" रावत प्रकाशन जयपुर (राज.)
8. कपूर, धर्मवीरसिंह (1997) " गैर सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण विकास" रावत प्रकाशन जयपुर (राज.)